इलाहाबाद से आते हैं, लेकिन हमारे भोपाल में उपराष्ट्रपति जी पैदा हुए। अभी जो स्टेशन है उसको मॉडल स्टेशन में शामिल किया जा रहा है या नहीं? भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसके बारे में मैं पूछना चाहता था। ...

श्री सभापति : अब दूसरा सवाल आ गया है।

दसवें रेलवे जोन की स्थापना

*204. **कुमारी सईदा खातून**†:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सरकार रेलवे का दसवां जोन स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बिलासपुर, मध्य प्रदेश से इस बारे में कोई मांग आई है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Railways Reforms Committee recommended the creation of four more zones but financial constraints preclude the possibility of going in for any new zone for the time being.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Sir.

कुमारी सईदा खातून : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो कहा गया है उसमें रेल सुधार के लिए उन्होंने चार जोनों के सृजन की स्थापना की सिफारिश की गई है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं जानना चाहती हूं कि वे चार जोन कौन-कौन से हैं जिनकी स्थापना की सिफारिश की गई है और क्या उनमें बिलासपुर जोन भी आता है? इन चार जोनों की स्थापना में प्रायोरिटी क्या रखी गई है और कितने किलोमीटर ऐवरेज दायरे में ये आते हैं?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, the four recommended zones are the East-Central Railway at Jabalpur. Then, North-Western Railway at Ajmer. Then, North-Central Railway at Allahabad and South-Western Railway at Bangalore. These four zones have been recommended. However, Railways have not taken a decision yet because of the involvement of huge amount for the creation of a zone.

कुमारी सईदा खातून: सभापति महोदय, इन्होंने कहा है कि वित्तीय तंगी के कारण फिलहाल किसी भी जोन की स्थापना करना संभव नहीं है। तो यह कब तक संभव होगा उसकी मैं जानकारी चाहती हूं और बिलासपुर जोन जो 6 राज्यों को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, तो इसकी स्थापना करने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है। इसकी मॉनिटरिंग किस ढंग से की जाएगी, उसकी क्या व्यवस्था रखी गई है, इसमें कितने डिवीजन होंगे, यह जानकारी भी मंत्री जी देने की कृपा करेंगे?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, when the resource position improves, the Railways will be able to think about these things. And while thinking about them, they can keep in view Bilaspur also.

श्रीमती वीणा वर्मा : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिलासपुर मंडल काफी समय से उपेक्षित हो रहा है। यद्यपि देश में 58 मंडलों में यह सबसे अधिक आय देने वाला मंडल है और यहां से सिर्फ वैगन लोडिंग से 156 करोड़ रुपये प्रति दिन का मुनाफा होता है। इसमें लोहा, सीमेंट के बहुत से संयंत्र है। यहां से कोयला सारे देश को पहुंचता है और जो देश का राइस बाउल छत्तीसगढ़ का प्रमुख भाग है, बिलासपुर का अलग जोन बनाने से बहुत लाभदायक होगा। यहां पर नये जोन बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या रेलवे सुधार समिति ने बिलासपुर को रेलवे का नया जोन बनाने की मांग पर विचार किया था? यदि हां, तो इसे किस आधार पर अस्वीकृत किया गया? इसका "बी" पार्ट यह है कि विशेषरूप से जब तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया जी ने मौटेतौर पर यह आश्वासन दिया था कि जब भी कोई नया जोन दिया जायेगा तो बिलासपुर को दिया जायेगा। अतः मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि यह आश्वासन कब तक पूरा करेंगे?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, this is what I have earlier informed. The Railway Reforms Committee has recommended to have the East-Central Railway Zone at Jabalpur. However, representations have come representing that the Zone should be established at Bilaspur. No final decision has yet been taken by the Railways because of the resource crunch. Whenever the position improves, we will think about it.

श्रीमती वीणा वर्मा : आश्वासन का क्या हुआ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो आश्वासन दिया गया था कि पहला जोन जब भी बनाया जायेगा वह बिलासपुर को दिया जायेगा। (**व्यवधान**) इन्होंने अभी कहा है कि चार जोन बनाये जा रहे हैं और उसमें जबलपुर भी शामिल है तो जो बिलासपुर के लिए

† सभा में यह प्रश्न कुमारी सईदा खातून द्वारा पूछा गया।

आश्वासन दिया गया था कि पहले उसको बनाया जायेगा उसका क्या हुआ?

श्री सभापति : जब नया बनायें तो इस पर विचार करें।

श्री मल्लिकार्जुन : जरूर विचार करेंगे।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: If, by any chance, a zone is created with headquarters at Bangalore, Guntur, Hubli, Solapur and other areas, which are hitherto in the South-Central Railway, are likely to be included in that zone. In that case, is there any proposal under the consideration of the Government to see that the Waltair Division is delinked from the South-Eastern Railway and clubbed to the South-Central Railway to get more homogeneity in the working of the South-Central Railway Zone?

SHRI MALLIKARJUN: So far as this Bangalore Zone is concerned, we have not formulated anything as to from which railway what division should be added and so on and so forth. So far as the inclusion of Waltair in the South-Central Railway is concerned, operationally it is not possible.

*205. *[Transferred to 17th March, 1992]*

MR. CHAIRMAN: Question No. 206.

*206 [The questioner (Shri Ashwani Kumar)] was absent. *[For answer* vide *col. No. 27 infra)*

Recommendations of Kelkar Committee on Gas Pricing

*207. SHRI PRAMOD MAHAJAN: SHRI VITHALBHAI M. PATEL:†

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what are the recommendations of the Kalkar Committee on gas pricing;

(b) what decisions have been taken thereon;

(c) whether Government have fixed a lower price of gas *vis-a-vis* the recommendations of the Kelkar Committee;

(d) whether the Gujarat Government has opposed the increased price of gas; and

(e) what was the price of gas during 1990-91?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Vithalbhai M. Patel.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (e) Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) (i) Price at landfall point: Rs. 1600/1000 M^3 plus increase by Rs. 200/1000 M^3 every year for 2 years.

(ii) Additional price on HBJ Pipeline: Rs. 850/1000 M^3

(iii) Price in North Eastern States: Rs. 1000/1000 M^3 with a discount of Rs. 400/1000 M^3 on case to case basis.

(b) (i) Price at landfall point: Rs. 1550/1000 M^3 plus increase by Rs. 100/1000 M^3 every year for 3 year.

(ii) Additional price on HBJ Pipeline. Rs. 850/1000 M^3

(iii) Price in North Eastern States: Rs. 1000/1000 M^3 with a discount of Rs. 400/1000 M^3 on case to case basis.

(c) and (d) Yes, Sir.

(e) (i) Price at landfall point: 1400/1000 M^3

(ii) Additional price on HBJ: Rs. 850/1000 M^3

(iii) Price in North Eastern States: Rs. 1000/1000 M^3 with discount of Rs. 500/1000 M^3 on case to case basis.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL: May I know from the hon. Minister...(*Interruptions*). Mr. Minister, please listen. Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister what the criteria adopted are by the Kelkar Committee to finalise the process on this?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, the Kelkar Committee had been given detailed terms of reference based on balancing the interests of suppliers and users, keeping in view the need for a remunerative return to the producer, etc. The recommendations of the Kelkar Committee were examined by a